RAJYA SABHA

Wednesday, the 5th December, 2001/14 *Agrahayana,* 1923 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: We will take up Question Nos. 221, 222 and 223 together, as all these questions relate to power.

पन बिजली संभावना

††*221. **श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य ':†**
डा. कुमकुम राय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में 84000 कि.वा. की पनबिजली की संभावना है और इसमें से केवल 17 प्रतिशत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका दोहन न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की इस संभावना के दोहन करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार से?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभू): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अधिष्ठापित क्षमता के संबंध में देश आर्थिक दृष्टि से दोहन योग्य 148700 मेगावाट ल्यांकित व्यवहार्य जल विद्युत शक्यता से सम्पन्न है। तथापि इस शक्यता के 16.6% का ही दोहन किया गया है, 6.3% विकास की विभिन्न अवस्थाओं में है और 2.73% के लिए केन्द्रीय विद्युत ाधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(ख) तकनीकी समस्याओं, भू-वैज्ञानिकी कठिनाईयों एवं घटनाओं, स्थलों की दुर्गमता, भूमि धिग्रहण में विलम्ब, पर्यावरणीय पहलू, परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना और ाद प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की समस्याओं के कारण जल विद्युत विकास बाधित रहा है।

(ग) और (घ) भारत सरकार देश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता

†सभा में यह प्रश्न श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य' द्वारा पूछा गया।

††प्रश्न सं. 221, 222 और 223 पर साथ-साथ चर्चा की गई।

प्रदान कर रही है और भारत सरकार ने अभी तक दसवीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए 16291 मेगावाट क्षमता और ग्यारहवीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए 22364 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं का अनंतिम रूप से पता लगाया है। तथापि इन योजनाओं में लाभ के लिए अभिज्ञात की गयी क्षमता अभिवृद्धि सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने, परियोजना प्रोत्साहनों और आवश्यक निधियां सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगा।

नये जल विद्युत स्थलों के सर्वेक्षण एवं जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने और व्यवहार्य परियोजनाओं, जिनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका, का एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए कुल लगभग 1,07,000 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता हेतु लगभग 400 जल विद्युत स्कीमों के संबंध में के.वि.प्रा. ने प्राथमिक दर्जा निर्धारण अध्ययन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, इन स्कीमों को अभिज्ञात किया गया था लेकिन अभी इनका विकास किया जाना है। इस अध्ययन कार्य से संभाव्य जल विद्युत विकासकर्त्ता चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक बेसिन में अति आकर्षक और व्यवहार्य स्कीमों के संबंध में विस्तृत जांच एवं सर्वेक्षण कार्य कर सकेंगे और लागत अनुमान तथा अनंतिम टैरिफ तैयार कर सकेंगे। सरकार राज्यों, वित्तीय संस्थानों और उद्यमियों के साथ व्यापक परामर्श करके जल विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण और क्रियान्वयन करने की विभिन्न संभावनाओं का पता लगा रही है। गैर-जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी, 2002 में आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है।

Hydro Power Potential

†*221. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA':††
SHRIMATI KUM KUM RAI:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that country has a potential of 84000 KW of hydro power and only 17 per cent out of this is being generated;

(b) if so, the reasons for not tapping this potential;

(c) whether Government have any plan for tapping this potential; and

(d) if so, by when and in what manner?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SURESH PRABHU): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajnath Singh 'Surya'

Statement

(a) The country is endowed with an economically viable hydro potential assessed at 148700 MW in terms of installed capacity. However, only 16.6% of this potential has been harnessed, 6.3% is under various stages of development and 2.73% has been cleared by the Central Electricity Authority (CEA).

(b) Hydro power development has been constrained on account of technical problems, geological difficulties and surprises, inaccessibility of sites, delay in land acquisition, environmental considerations, resettlement of project affected families, and law and order problems in militant infested areas.

(c) and (d) Government of India is according high priority for development of hydro-electric projects in the country and has so far tentatively identified hydro-electric projects of 16,291 MW for benefits in the Xth Plan and 22,364 MW for benefits in the XIth Plan. The capacity addition identified for benefits in these Plans would however depend on obtaining statutory clearances, project initiatives and tying-up of necessary funds.

In order to accelerate the process of survey and investigation of the new hydro-electric sites and to create a shelf of feasible projects which could be taken up for execution, the CEA has brought out a Report on Preliminary Ranking Study of about 400 hydro schemes with an aggregate installed capacity of about 1,07,000 MW which were identified but are yet to be developed. This study would enable potential hydro developers to take up detailed survey and investigation, cost estimates and tentative tariff for the most attractive and viable schemes in each basin in a phased manner. The Government is exploring various possibilities of funding and executing hydro-electric projects after extensive consultations with the States, financial institutions and entrepreneurs. An International Conference on non-fossil fuel Generation has been scheduled in February, 2002.

Shortfall of power supply in Andhra Pradesh

*222. SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether as per Central Electricity Authority, Andhra Pradesh, faced 20 per cent shortfall of power supply, the third highest in India; and

(b) if so, whether the State Government has requested that Central Government to release more power for Andhra Pradesh so that the demands of the State farmers and other consumers are fully met?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SURESH PRABHU): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.